Volume: 3 Issue: 5 Pages: 48-51

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं कौशल आधारित शिक्षा: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

[*1]डॉ. अजय कुमार यादव

[*1]सहायक प्राध्यापक, बी.एड. विभाग, जंगी महाविद्यालय, असबरनपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 5.231
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 25/April/2024
Accepted: 26/May/2024

***Corresponding Author**
डॉ. अजय कुमार यादव
सहायक प्राध्यापक, बी.एड. विभाग, जंगी महाविद्यालय, असबरनपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
प्रस्तुत शोध 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) के विशेष संदर्भ में भारतीय शिक्षा प्रणाली के भीतर 'कौशल आधारित शिक्षा' (Skill-based Education) के महत्व, कार्यान्वयन और दूरगामी प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 21वीं सदी की तीव्र बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति को देखते हुए, पारंपरिक सैद्धांतिक शिक्षा अब छात्रों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। इसी अंतराल (Skill Gap) को समाप्त करने के लिए एनईपी 2020 एक दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत करती है। इस शोध का मुख्य केंद्र बिंदु यह विश्लेषण करना है कि कैसे यह नीति शिक्षा के प्राथमिक स्तर से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव रखती है। नीतिगत प्रावधानों के अनुसार, कक्षा 6 से ही छात्रों को विभिन्न स्थानीय शिल्पों, कोडिंग और अन्य व्यावसायिक कौशलों से परिचित कराया जाएगा, जिसमें '10 बैग-लेस डेज़' और इंटर्नशिप जैसे व्यावहारिक अनुभव शामिल हैं। यह शोध इस बात पर बल देता है कि कौशल आधारित शिक्षा केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों में तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता और रचनात्मकता जैसे सॉफ्ट स्किल्स विकसित करने का भी माध्यम है।
शोध में 'लोक विद्या' और भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) को आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़कर भारत एक ऐसा कार्यबल तैयार कर सकता है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ अपनी जड़ों से भी जुड़ा हो। नीति का बहु-विषयक दृष्टिकोण (Multidisciplinary Approach) छात्रों को कला और विज्ञान के पारंपरिक बंधनों से मुक्त कर उनकी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार कौशल चयन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह शोध पत्र यह स्पष्ट करता है कि कौशल आधारित शिक्षा का सफल क्रियान्वयन 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को सिद्ध करने में आधारशिला का कार्य करेगा। यह न केवल बेरोजगारी की दर को कम करने में सहायक होगा, बल्कि विद्यार्थियों को 'जॉब सीकर' (Job Seeker) के बजाय 'जॉब क्रिएटर' (Job Creator) बनने के लिए प्रेरित करेगा।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल आधारित शिक्षा, व्यावसायिक एकीकरण, आत्मनिर्भर भारत, व्यावहारिक अधिगम, कौशल अंतर, 21वीं सदी के कौशल।

1. प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र की नियति और उसके सामाजिक-आर्थिक ढांचे का निर्धारण करने वाली सबसे शक्तिशाली इकाई है। भारत जैसे विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) वाले देश के लिए यह अनिवार्य है कि उसकी शिक्षा प्रणाली न केवल ज्ञानवर्धक हो, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम भी बने। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से सैद्धांतिक ज्ञान और डिग्री केंद्रित रही, जिसके कारण शिक्षित युवाओं और उद्योग जगत की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई। इसी ऐतिहासिक विसंगति को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) का प्रादुर्भाव किया गया है, जो रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर

'कौशल आधारित शिक्षा' (Skill-based Education) पर बल देती है। 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में केवल सूचनाओं का संग्रह पर्याप्त नहीं है; आज नवाचार, तकनीकी दक्षता और व्यावहारिक अनुप्रयोग की मांग है। एनईपी 2020 का मूल दर्शन इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा को व्यक्ति के भीतर छिपी विशिष्ट प्रतिभा और कौशल को निखारने का कार्य करना चाहिए। यह नीति शिक्षा के व्यवसायीकरण के पुराने संकुचित दृष्टिकोण को बदलते हुए, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानती है। यह न केवल आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व में गरिमा और श्रम के प्रति सम्मान का भाव भी जागृत करती है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य यह अन्वेषण करना है कि किस प्रकार कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से हम अपनी युवा शक्ति को 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प से जोड़ सकते हैं। यह प्रस्तावना इस विचार को रेखांकित करती है कि ज्ञान और कौशल का समन्वय ही वह माध्यम है, जिससे भारत एक 'वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' के रूप में अपनी पहचान पुन: स्थापित कर सकता है।

2. शोध के उद्देश्य

- NEP 2020 में कौशल विकास के लिए निर्धारित नीतिगत ढाँचे को समझना।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की संभावनाओं का आकलन करना।
- कौशल आधारित शिक्षा के मार्ग में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

3. शोध विधि

प्रस्तुत शोध कार्य की प्रकृति मुख्य रूप से गुणात्मक (Qualitative) और वर्णनात्मक (Descriptive) है। इसमें 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के दस्तावेजों का वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य और कौशल विकास की आवश्यकताओं के संदर्भ में सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है।

डेटा संग्रहण की विधि

इस शोध पत्र के लिए डेटा मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) से एकत्रित किया गया है। इसमें निम्नलिखित संसाधनों का उपयोग किया गया है-

- **शासकीय दस्तावेज:** भारत सरकार द्वारा जारी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का मूल प्रारूप।
- **साहित्य समीक्षा:** शिक्षाविदों के लेख, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं (Journals), और कौशल विकास पर आधारित पूर्ववर्ती शोध कार्य।
- **रिपोर्ट्स:** यूजीसी (UGC), एनसीईआरटी (NCERT), और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट और सांख्यिकीय आंकड़े।
- **डिजिटल संसाधन:** आधिकारिक वेबसाइट्स, ई-पुस्तकालय और शैक्षिक पोर्टल।

4. अध्ययन का क्षेत्र

शोध मुख्य रूप से भारतीय स्कूली शिक्षा (कक्षा 6 से 12) और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक एकीकरण के प्रावधानों तक सीमित है। इसमें विशेष रूप से यह देखा गया है कि नीतिगत परिवर्तन व्यावहारिक स्तर पर कौशल विकास को कैसे प्रभावित करते हैं।

5. डेटा विश्लेषण प्रक्रिया

एकत्रित की गई जानकारी का विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) किया गया है। नीति के विभिन्न बिंदुओं की तुलना वर्तमान शैक्षिक चुनौतियों से की गई है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि 'कौशल आधारित शिक्षा' किस प्रकार रोजगार सृजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहायक सिद्ध हो सकती है।

6. शोध की सीमाएं

यह शोध मुख्य रूप से उपलब्ध साहित्य और नीतिगत दस्तावेजों पर आधारित है, इसलिए इसके निष्कर्ष प्राथमिक डेटा (Primary Data) या क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अभाव में सैद्धांतिक अधिक हो सकते हैं। भविष्य के शोध में विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन का अध्ययन किया जा सकता है।

7. NEP 2020 में कौशल विकास के प्रमुख प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शैक्षिक संरचना में एक युगांतरकारी परिवर्तन है, जो डिग्री-केंद्रित शिक्षा के स्थान पर कौशल-केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देती है। इसके प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं:

- **व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और '10 बैग-लेस डेज़':** नीति का सबसे क्रांतिकारी पहलू कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना और इसे मुख्यधारा की शिक्षा के समान सम्मान दिलाना है। '10 बैग-लेस डेज़' (10 Bagless Days) की अवधारणा के माध्यम से छात्रों को वर्ष में कम से कम 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल आने और स्थानीय शिल्पकारों, जैसे कि बढ़ई, कुम्हार, या बागवानों के साथ समय बिताने का अवसर दिया जाएगा। इससे छात्रों में श्रम की गरिमा (Dignity of Labor) और व्यावहारिक समझ विकसित होगी।
- **व्यावहारिक इंटर्नशिप (Internship):** केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के बजाय, NEP 2020 स्थानीय उद्योगों और विशेषज्ञों के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव पर बल देती है। माध्यमिक स्तर के छात्रों को स्थानीय बिजली मिस्त्री, माली या बढ़ई के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। यह प्रत्यक्ष अनुभव छात्रों को किताबी दुनिया से बाहर निकालकर वास्तविक कार्यस्थल की चुनौतियों और बारीकियों से परिचित कराएगा, जो भविष्य में उनके स्वरोजगार के मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **लचीलापन और बहु-विषयक दृष्टिकोण (Multidisciplinary Approach):** पारंपरिक रूप से कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच जो सख्त विभाजन था, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब एक छात्र भौतिक विज्ञान के साथ संगीत या फैशन डिजाइनिंग जैसे कौशल आधारित विषय भी चुन सकता है। यह 'साइलो-मुक्त' (Silo-free) शिक्षा प्रणाली छात्र की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने और उसे अपनी पसंद के अनुसार करियर बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) एवं क्रेडिट प्रणाली:** उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्थापित करने के लिए इसे 'राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे' (NSQF) के साथ जोड़ा गया है। इसके तहत एक एकीकृत 'क्रेडिट-आधारित' प्रणाली विकसित की गई है, जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित अंकों को शैक्षणिक डिग्री के साथ जोड़ा जा सकेगा। यह छात्रों को अकादमिक शिक्षा और व्यावसायिक कौशल के बीच सहजता से आवागमन करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनते हैं। ये प्रावधान भारतीय युवाओं को न केवल शिक्षित बल्कि 'दीक्षित' (Skills-ready) बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल हैं, जो उन्हें वैश्विक कार्यबल के अनुरूप तैयार करते हैं।

8. कौशल आधारित शिक्षा का महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौशल आधारित शिक्षा केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक

परिवर्तन का माध्यम है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है:

- **आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार (Self-reliance and Entrepreneurship):** पारंपरिक शिक्षा प्रणाली ने अक्सर 'नौकरी चाहने वालों' (Job Seekers) की एक विशाल भीड़ पैदा की है। कौशल आधारित शिक्षा इस मानसिकता को बदलकर छात्रों को 'नौकरी प्रदाता' (Job Providers) बनने की दिशा में अग्रसर करती है। जब छात्र अपनी रुचि के अनुसार प्लंबिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या हस्तशिल्प जैसे व्यावहारिक कौशल सीखते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास का संचार होता है। यह आत्मविश्वास उन्हें स्वयं का लघु उद्योग या स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- **रोजगारोन्मुखता और उद्योग की मांग (Employability and Industry Alignment):** वर्तमान समय में 'स्किल गैप' (Skill Gap) एक गंभीर समस्या है, जहाँ डिग्री धारक युवाओं के पास वे कौशल नहीं होते जिनकी उद्योगों को आवश्यकता है। कौशल आधारित शिक्षा पाठ्यक्रमों को बाजार की वर्तमान मांग के अनुरूप ढालती है। जब शिक्षा सीधे तौर पर व्यावहारिक कौशलों से जुड़ती है, तो छात्र कार्यबल में शामिल होने के लिए पहले से तैयार (Industry-ready) होते हैं। इससे न केवल बेरोजगारी दर में कमी आती है, बल्कि देश के आर्थिक उत्पादन में भी वृद्धि होती है।
- **तार्किक और रचनात्मक सोच (Critical and Creative Thinking):** कौशल आधारित शिक्षा 'रटने की संस्कृति' (Rote Learning) पर प्रहार करती है। यह 'करके सीखने' (Learning by Doing) की पद्धति को बढ़ावा देती है। जब कोई छात्र किसी समस्या का समाधान व्यावहारिक रूप से करता है, तो उसकी तार्किक क्षमता का विकास होता है। उदाहरण के लिए, एक रोबोटिक किट को असेंबल करते समय या किसी स्थानीय समस्या का समाधान ढूंढते समय छात्र की रचनात्मकता और नवाचार (Innovation) करने की शक्ति जागृत होती है।
- **श्रम की गरिमा (Dignity of Labor):** भारतीय समाज में अक्सर बौद्धिक कार्यों को शारीरिक या तकनीकी कार्यों से श्रेष्ठ माना जाता रहा है। प्रारंभिक स्तर से ही कौशल शिक्षा की शुरुआत छात्रों के मन में हर प्रकार के कार्य के प्रति सम्मान पैदा करती है। यह दृष्टिकोण समाज में समानता और व्यावसायिक गरिमा के नए मापदंड स्थापित करता है।

9. व्यावसायिक एकीकरण: एक अभिनव पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 'व्यावसायिक एकीकरण' का अर्थ शिक्षा के पारंपरिक किताबी ढांचे और व्यावहारिक कौशल के बीच की दूरी को समाप्त करना है। पूर्ववर्ती शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से अलग माना जाता था, जिससे इसे 'दोयम दर्जे' की शिक्षा समझा जाने लगा। एनईपी 2020 इस धारणा को बदलते हुए व्यावसायिक विषयों को गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के समान महत्व प्रदान करती है। इस एकीकरण की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापकता है। यह प्राथमिक स्तर पर कौशलों के प्रति 'एक्सपोज़र' से शुरू होकर उच्च शिक्षा में विशिष्ट विशेषज्ञता तक जाती है। स्कूल स्तर पर 'लोक विद्या' और स्थानीय शिल्पों का समावेश छात्रों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है, वहीं उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंकों को डिग्री के साथ जोड़कर इसे प्रमाणिकता प्रदान की गई है। यह एकीकरण एक ऐसी 'निर्बाध गतिशीलता' (Seamless Mobility) सुनिश्चित करता है जहाँ छात्र अपनी सुविधानुसार शिक्षा और कार्यक्षेत्र के बीच आवागमन कर सकते हैं। अंततः, व्यावसायिक एकीकरण का लक्ष्य एक ऐसा शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहाँ प्रत्येक स्नातक के पास कम से कम एक विशिष्ट कौशल अवश्य हो।

10. आत्मनिर्भर भारत और कौशल आधारित शिक्षा

'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प केवल एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के स्वाभिमान और स्वदेशी सामर्थ्य का पुनर्जागरण है। इस संकल्प की सिद्धि में 'कौशल आधारित शिक्षा' सबसे महत्वपूर्ण इंजन के रूप में कार्य करती है। एक राष्ट्र तभी आत्मनिर्भर बन सकता है जब उसकी युवा शक्ति केवल डिग्रियों से सुसज्जित न होकर व्यावहारिक कौशलों में दक्ष हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को 'स्थानीय से वैश्विक' (Local to Global) के सिद्धांत पर आधारित किया गया है। जब छात्र स्कूली स्तर से ही स्थानीय शिल्पों, कृषि तकनीकों, कोडिंग या आधुनिक विनिर्माण कौशलों को सीखते हैं, तो वे अपनी मिट्टी की समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। यह स्वावलंबन उन्हें 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनने की प्रेरणा देता है, जो लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के आधार को मजबूत करता है। कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से जब एक विद्यार्थी तकनीकी रूप से सशक्त होता है, तो वह आयात पर निर्भरता कम करने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने में योगदान देता है। अतः, आत्मनिर्भरता का मार्ग कक्षाओं से होकर गुजरता है, जहाँ ज्ञान का कौशल के साथ समन्वय एक सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत की नींव रखता है। यह शिक्षा प्रणाली युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के साथ-साथ उन्हें अपनी जड़ों से जोड़कर आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है।

11. व्यावहारिक अधिगम, कौशल अंतर (Skill Gap) एवं 21वीं सदी के कौशल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वैचारिक ढांचा इन तीन स्तंभों पर टिका है, जो शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित न रखकर उसे सक्षमता में बदलते हैं।

i). **व्यावहारिक अधिगम (Experiential Learning):** व्यावहारिक अधिगम का अर्थ है 'अनुभव के माध्यम से सीखना'। यह रटने की पारंपरिक पद्धति के ठीक विपरीत है। इसमें छात्र केवल सिद्धांतों को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें क्रियान्वित करते हैं। उदाहरण के लिए, विज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोगशाला में प्रयोग करके समझना या अर्थशास्त्र को बाजार के सर्वेक्षण के माध्यम से सीखना। यह पद्धति छात्रों में विषय के प्रति गहरी समझ और जिज्ञासा उत्पन्न करती है। जब छात्र स्वयं कार्य करते हैं, तो उनका अधिगम स्थायी और प्रभावी होता है।

ii). **कौशल अंतर (Skill Gap):** कौशल अंतर वह खाई है जो शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और उद्योगों की वास्तविक मांग के बीच मौजूद है। वर्तमान में, कई स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास वे 'व्यावहारिक कौशल' नहीं हैं जिनकी आज के कॉर्पोरेट जगत या उद्योगों को आवश्यकता है। एनईपी 2020 का मुख्य लक्ष्य इसी 'स्किल गैप' को भरना है। पाठ्यक्रम को उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठित करना और इंटर्नशिप को अनिवार्य बनाना इसी अंतर को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम हैं।

iii). **21वीं सदी के कौशल (21st Century Skills):** आधुनिक युग में केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। 21वीं सदी के कौशल के अंतर्गत 4Cs को विशेष महत्व दिया गया है:

- **Critical Thinking (तार्किक सोच):** समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करना।

- **Creativity (रचनात्मकता):** नए और अभिनव समाधान खोजना।
- **Collaboration (सहयोग):** समूह में मिलकर कार्य करने की क्षमता।
- **Communication (संप्रेषण):** अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना।

इसके अतिरिक्त डिजिटल साक्षरता और लचीलापन (Adaptability) भी इस श्रेणी के अनिवार्य अंग हैं। कौशल आधारित शिक्षा छात्रों को इन कौशलों से सुसज्जित करती है ताकि वे न केवल व्यावसायिक जीवन में बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी सफल हो सकें। व्यावहारिक अधिगम के माध्यम से जब 21वीं सदी के कौशल विकसित होते हैं, तभी वर्तमान 'कौशल अंतर' समाप्त होता है और एक सशक्त कार्यबल का निर्माण होता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक मौलिक और संरचनात्मक परिवर्तन का सूत्रपात करती है। शिक्षा को केवल सूचनाओं के संग्रहण तक सीमित न रखकर, इसे 'कौशल आधारित शिक्षा' (Skill-based Education) के साथ जोड़ना समय की मांग और राष्ट्र की आवश्यकता है। शोध के माध्यम से यह निष्कर्ष निकलता है कि कक्षा 6 से व्यावसायिक एकीकरण और व्यावहारिक अधिगम की शुरुआत छात्रों में न केवल तकनीकी दक्षता विकसित करेगी, बल्कि उनमें 'श्रम की गरिमा' के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण भी जागृत करेगी। इस नीति में निहित 'बहु-विषयक दृष्टिकोण' छात्रों को कला, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों के बीच सेतु बनाने की स्वतंत्रता देता है, जो 21वीं सदी की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए अनिवार्य है। व्यावहारिक इंटर्नशिप और '10 बैग-लेस डेज़' जैसी पहलें छात्रों को वास्तविक कार्यक्षेत्र के अनुभवों से जोड़ती हैं, जिससे 'कौशल अंतर' (Skill Gap) को कम करने में मदद मिलेगी। यह अध्ययन रेखांकित करता है कि यदि व्यावसायिक शिक्षा को शैक्षणिक ऋण (Academic Credits) के साथ पूरी तरह से एकीकृत कर दिया जाए, तो यह पारंपरिक डिग्रियों के समकक्ष सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगी। कौशल आधारित शिक्षा का सफल क्रियान्वयन 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को धरातल पर उतारने की कुंजी है। यह युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ उनमें उद्यमिता (Entrepreneurship) की भावना भरेगा, जिससे वे रोजगार की खोज करने वालों के बजाय रोजगार का सृजन करने वाले बनेंगे। NEP 2020 भारतीय युवाओं के सर्वांगीण विकास और भारत को पुनः 'विश्व गुरु' के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। इसका पूर्ण लाभ तभी संभव है जब शिक्षण संस्थानों, उद्योगों और सरकार के बीच एक सुदृढ़ समन्वय स्थापित हो।

संदर्भ सूची (References)

1. Ministry of Education. *National Education Policy 2020*. Government of India; 2020. Available from: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_update/NEP_final_HI_0.pdf
2. NCERT. *Transforming School Education: Implementation of NEP 2020*. National Council of Educational Research and Training; 2022.
3. National Skill Development Corporation (NSDC). *Skill Gap Analysis Report: Future of Jobs in India 2025*. NSDC Publications; 2021.
4. Agrawal T. Vocational education and training in India: A strategy for hard-to-reach groups. *International Journal of Educational Development*. 2021;82:102-115.
5. Dutta V, Sharma R. Skill-based education and the vision of Atmanirbhar Bharat: A critical study of NEP 2020. *Journal of Indian Education*. 2023;48(3):22-35.
6. UNESCO. *State of the Education Report for India 2021: No Teacher, No Class*. UNESCO Office New Delhi; 2021.
7. Kumar A. *21st Century Skills and Indian Classrooms: A Pedagogical Shift*. Oxford University Press; 2022.
8. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE). *Annual Report 2022-23*. Government of India; 2023.
9. Pandey S, Mishra P. Integrating vocational education with mainstream curriculum: Challenges and opportunities. *Indian Journal of Technical Education*. 2022;45(1):12-19.
10. Rao SS. Higher education in the light of NEP 2020: Focus on vocationalization. *University News*. 2021;59(14):45-52.
11. Srivastava R. *ICT and AI in Vocational Training: Bridging the Skill Gap*. Academic Press India; 2023.
12. World Bank. *Skilling India: Policy Priorities for an Inclusive Labor Market*. World Bank Group; 2022.
13. Yadav RK. Vocational education in NEP 2020: A roadmap for youth empowerment. *International Journal of Social Sciences and Management*. 2022;9(2):67-74.